

ब्याज टुडे

मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने तरलता बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए

समिति ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 100 बेसिस पॉइंट्स (bps) और रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने का निर्णय लिया।

तरलता प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतिगत उपकरण

➤ नकद आरक्षित अनुपात (CRR): यह किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह अनुपात है, जिसे उसे नकदी के रूप में RBI के पास जमा करना होता है।

⊕ बैंक CRR धन को कॉरपोरेट या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार नहीं दे सकते तथा न ही उसे निवेश के उद्देश्यों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि RBI इस धन पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है।

➤ रेपो दर: रेपो दर (पुनर्खरीद दर), वह ब्याज दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर अल्पकालिक समय के लिए उधार देता है। यह आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर दिया जाता है।

➤ तरलता समायोजन सुविधा (LAF): LAF से तात्पर्य RBI के उन कार्यों से है, जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में/ से तरलता को बढ़ाता है/ कम करता है।

⊕ इसमें ओवरनाइट के साथ-साथ टर्म रेपो/ रिवर्स रेपो (निश्चित और परिवर्तनीय दरें), SDF एवं MSF भी शामिल हैं।

➤ सांविधिक तरलता अनुपात (SLR): यह जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है, जिसे वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है।

⊕ इसे RBI के पास जमा नहीं करना होता है, बल्कि बैंक इसे अपने पास ही रखते हैं। SLR का निर्धारण RBI द्वारा ही तय किया जाता है।

➤ अन्य उपकरण: बैंक दर, स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs), आदि।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में

➤ कानूनी प्रावधान: संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (2016 में संशोधित)।

➤ संरचना: RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति।

⊕ RBI से 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

➤ बैठकें: MPC को वर्ष में कम-से-कम 4 बार बैठक करना आवश्यक है।

⊕ MPC की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का है।

भारत में तेजी से बढ़ता व्चिक कॉमर्स उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है

कंसल्टेंसी फर्म कियर्नी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्यू-कॉमर्स किराना बाजार के 2024-27 के बीच तीन गुना बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉमर्स/ ऑन-डिमांड डिलीवरी) के बारे में

➤ अर्थ: यह एक अनूठा व्यवसाय मॉडल है, जो ऑर्डर करने के 10-30 मिनट के भीतर सामान/ सेवाएं डिलीवर करता है। उदाहरण के लिए- स्विगी का इंस्टामार्ट, ब्लिंकित, जेट्रो आदि।

⊕ इसमें विक्रेता बाहरी इलाकों में स्थित पारंपरिक गोदामों का उपयोग नहीं करते, बल्कि डिलीवरी बिंदु के पास ही अवस्थित लघु गोदामों का उपयोग करते हैं।

क्यू-कॉमर्स की प्रमुख परिवर्तनकारी भूमिका

➤ उपभोक्ताओं का व्यवहार बेहतर सुविधा और तत्काल संतुष्टि से प्रेरित होता है।

⊕ वृद्धिशील बिक्री: क्यू-कॉमर्स के माध्यम से होने वाली सभी बिक्री का 6-8% विशुद्ध रूप से वृद्धिशील है। यह स्लैकिंग, त्यौहार के समय खरीदारी, उपहार देने आदि से संचालित होता है।

◆ फलों, सब्जियों और डेयरी क्षेत्रों में इसे अपनाने की दर कम है, क्योंकि यहां खरीदने की क्षमता एवं ताजगी को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

⊕ प्रीमियम को ज्यादा महत्त्व देना: उच्च-स्तरीय ब्रांड्स तक आसान पहुंच तथा कुछ प्रीमियम उत्पाद सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च किए जाते हैं।

➤ रोजगार गतिशीलता को नया आकार देना

⊕ प्रत्यक्ष रोजगार नोड्स (लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स प्रमुख चालक है) और अप्रत्यक्ष रोजगार नोड्स (अतिरिक्त आईटी नौकरियां, आदि) दोनों का विकास हो रहा है।

◆ यह प्रति करोड़ रुपये मासिक सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) पर 62-64 लोगों को रोजगार देता है, जो ई-कॉमर्स (25-29 लोग) से अधिक है।

⊕ रोजगार में संरचनात्मक बदलाव: निम्नलिखित के कारण प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स व्यवस्था को अपनाया जा रहा है-

◆ लचीलापन बढ़ता जा रहा है, जैसे अंशकालिक या पूर्णकालिक कार्य।

◆ हाइपरलोकल रोजगार वितरण, क्यू-कॉमर्स स्टोर पूरे क्षेत्र में वितरित होते हैं और ये केंद्रीकृत नहीं होते।

◆ मल्टी-प्लेटफॉर्म गिग वर्क में भाग लेने का अवसर मिलता है।

निष्कर्ष

क्यू-कॉमर्स में वृद्धि के कारण व्यवसायों ने अपनी निवेश रणनीतियों को इस ओर स्थानांतरित कर दिया है। फिर भी इसे अन्य खुदरा चैनलों के साथ सह-अस्तित्व में रहते हुए उपभोक्ता वरीयताओं और बाजार की गतिशीलता के साथ लगातार अनुकूलन करना होगा।

ऑफलाइन चैनलों की तुलना में क्यू-कॉमर्स के लाभ



सुविधा:

बहुत कम समय में तेज डिलीवरी व कम प्रतीक्षा समय।



वर्गीकरण:

उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला।



आपूर्ति श्रृंखला:

अनुकूलित लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी के कारण अपव्यय में कमी और लाभ में वृद्धि।

भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच 269 मिलियन लोग चरम-गरीबी से बाहर आए हैं

विश्व बैंक की नई गरीबी रेखा के आधार पर भारत में चरम गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारत में चरम गरीबी अनुपात 2011 के 27.1% से घटकर 2022 में 5.3% रह गया है। विश्व बैंक ने 2021 क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर 3 डॉलर दैनिक (उपभोग) स्तर को नई गरीबी रेखा माना है।

▶ वैश्विक गरीबी रेखाएं:

- ⊕ गरीबी रेखा वह आर्थिक सीमा होती है, जिसके नीचे व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है।
- ⊕ विश्व बैंक ने 3.00 डॉलर दैनिक (उपभोग) को नई गरीबी रेखा तय की है। इससे पहले 2017 की PPP के आधार पर 2.15 डॉलर दैनिक को गरीबी रेखा माना गया था।
- ⊕ निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा 4.20 डॉलर दैनिक तथा उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा 8.30 डॉलर दैनिक है।

▶ ग्रामीण-शहरी गरीबी में अंतर:

- ⊕ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 2011-12 की 18.4% से घटकर 2022-23 में 2.8% रह गई।
- ⊕ शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गई।

▶ बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI): MPI 2005-06 में 53.8% था, जो 2019-21 में घटकर 16.4% और 2022-23 में 15.5% हो गया।

- ⊕ यह 6 संकेतकों पर आधारित है: उपभोग/ आय, शिक्षा स्तर, स्कूलों में नामांकन, पेयजल की उपलब्धता, सैनिटेशन और बिजली।



भारत में चरम गरीबी में कमी का कारण बनी प्रमुख योजनाएं:

- ▶ प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY): इसका उद्देश्य सभी बेघर परिवारों को पक्के मकान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- ▶ प्रधान मंत्री उज्वला योजना (PMUY): इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना है।
- ▶ प्रधान मंत्री जनधन योजना (PMJDY): इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- ▶ आयुष्मान भारत योजना: इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज का आर्थिक बोझ उठाने से राहत मिली है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं भी प्राप्त हुई हैं।

RBI गवर्नर के अनुसार 2023-24 से 2024-25 के बीच भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 14% की वृद्धि दर्ज की गई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 14% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, 2024-25 में भारत में केवल 0.4 बिलियन डॉलर का निवल (नेट) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष से काफी कम है।

- ▶ भारत से पूंजी अन्य देशों में जाने के कारण विशुद्ध विदेशी निवेश में कमी दर्ज की गई। RBI के अनुसार, इस ट्रेड से संकेत मिलता है कि भारत का बाजार परिपक्व हो रहा है, जहां विदेशी निवेशक सरलता से निवेश कर सकते हैं और उतनी ही सरलता से पूंजी निकास कर सकते हैं।
- ▶ 2024-25 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) घटकर 1.7 बिलियन डॉलर रह गया था, क्योंकि निवेशकों ने इक्विटी में मुनाफा वसूली की थी।

भारत में 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)' क्या है?

- ▶ परिभाषा: भारत के बाहर के निवासियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में किया गया निवेश FDI माना जाता है:
 - ⊕ किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इक्विटी के माध्यम से निवेश, या
 - ⊕ किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों के जारी होने के बाद फुली डाइल्यूटेड आधार पर पेड अप कैपिटल के 10% या उससे अधिक का निवेश।
 - ◆ फुली डाइल्यूटेड शेयर किसी कंपनी के कुल सामान्य शेयरों की संख्या को दर्शाते हैं। इनमें शामिल होते हैं: वर्तमान में शेयरधारकों के पास मौजूद आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और वे संभावित शेयर्स, जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक ऑप्शंस आदि के रूपांतरण से प्राप्त किया जा सकता है।
 - ⊕ इसमें निवेशक अपने साथ तकनीक, ज्ञान और कौशल लाते हैं तथा व्यवसाय में आंशिक या पूर्ण स्वामित्व भी प्राप्त करते हैं।
- ▶ सकल और निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से आशय
 - ⊕ सकल FDI: विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत की उत्पादक परिसंपत्तियों में सीधे किया गया कुल निवेश।
 - ⊕ निवल FDI: यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत से बाहर जाने वाले निवेश का अंतर है।
 - ◆ भारत से बाहर जाने वाले निवेश में विदेशी कंपनियों द्वारा भारत से अपनी पूंजी निकासी और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश का योग है।

भारत में FDI वृद्धि के प्रमुख कारण:

- ▶ निवेश अनुकूल नीतिगत सुधार: अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति दी गई है। साथ ही, GST और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे सुधार भी लागू किए गए हैं।
- ▶ अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय: सेवा क्षेत्रों (वित्त, IT, अनुसंधान एवं परामर्श आदि) को निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया है। इसके अलावा, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI) लागू की गई है।
- ▶ राज्य-स्तरीय सुधार: राज्यों में अवसंरचना में सुधार, निवेशक आउटरीच, औद्योगिक नीति सुधार आदि के माध्यम से निवेश अनुकूल माहौल बनाया गया है।

2024-25 में भारत में FDI का प्रमुख ट्रेड

- ▶ भारत में FDI: 2024-25 में 81 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ।
- ▶ भारत में सबसे अधिक FDI करने वाले देश: सिंगापुर, इसके बाद मॉरीशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स आदि।
- ▶ सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश: महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु।

चौथी भारत-मध्य एशिया वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई

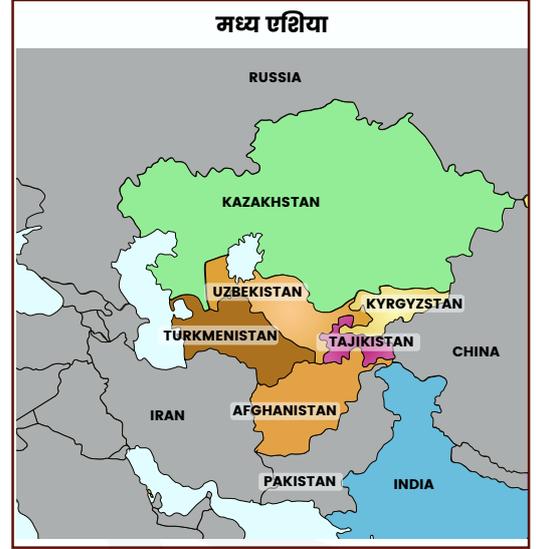
इस वार्ता में कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।

चौथी वार्ता के संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- ▶ मध्य एशियाई देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और दुर्लभ भू खनिजों एवं महत्वपूर्ण खनिजों की संयुक्त खोज में रुचि दिखाई।
- ▶ मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के अनुसार, 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष" के रूप में मनाने के निर्णय का स्वागत किया।
- ▶ मंत्रियों ने ताजिकिस्तान में हिमनद संरक्षण पर आयोजित पहले उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सराहना की। यह सम्मेलन 2025 को 'अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष' के रूप में मनाने का हिस्सा था।

भारत-मध्य एशिया संबंध:

- ▶ प्राचीन संबंध: मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध हजारों साल (लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) पुराने हैं। ये दोनों क्षेत्र रेशम मार्ग के जरिए आपस में जुड़े हुए थे।
 - ⊕ वर्तमान समय में, मध्य एशियाई गणराज्य भारत की विस्तारित पड़ोसी नीति का हिस्सा हैं।
- ▶ कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), चाबहार बंदरगाह जैसी पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र से संपर्क बढ़ाया है।
- ▶ ऊर्जा सुरक्षा: उदाहरण के लिए- TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन परियोजना। यह तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिश क्षेत्र से भारत तक प्राकृतिक गैस लाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
 - ⊕ भारत अपने परमाणु संयंत्रों के लिए 2009 से कजाकिस्तान से येलो केक (यूरैनियम ऑक्साइड) का आयात कर रहा है।
- ▶ व्यापार और आर्थिक सहयोग: उदाहरण के लिए- भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि, भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद की स्थापना आदि।
- ▶ सुरक्षा और रक्षा: यह सहयोग वार्षिक सैन्य अभ्यासों जैसे खंजर (भारत और किर्गिस्तान के बीच), "काजिंद" (भारत और कजाकिस्तान के बीच) आदि के माध्यम से किया जा रहा है।



अन्य सुर्खियां

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)

सरकार जल्द ही पुडुचेरी विधान सभा के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) शुरू करेगी।

- ▶ नागालैंड पहला राज्य था जिसने NeVA को सफलतापूर्वक लागू किया।

NeVA के बारे में:

- ▶ कार्यान्वयन मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय
- ▶ उद्देश्य: देश के सभी 37 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं की कार्यप्रणाली को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुव्यवस्थित और पेपरलेस बनाना और 'वन नेशन-वन एप्लीकेशन' की परिकल्पना को साकार करना।
- ▶ तकनीकी आधार: NIC क्लाउड 'मेघराज' पर होस्ट किया गया है। यह सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही सहजता से डिजिटल रूप में संचालित करने में सक्षम बनाता है।
- ▶ वित्तपोषण: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समान रूप से वित्तीय सहायता मिलती है।

30x30 लक्ष्य

हाल ही में, एक रिपोर्ट ने 2030 तक वैश्विक महासागरों के 30% की सुरक्षा के 30x30 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सालाना 15.8 बिलियन डॉलर निवेश करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। यह निवेश राशि वार्षिक वैश्विक रक्षा बजट के लगभग 0.5% के बराबर है।

30x30 लक्ष्य के बारे में

- ▶ यह लक्ष्य कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) का हिस्सा है। इस फ्रेमवर्क में 2050 तक के लिए 4 प्रमुख लक्ष्य और 2030 तक के लिए 23 कार्रवाई-उन्मुख वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं।
 - ⊕ KMGBF को जैविक विविधता अभिसमय (CBD) के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP 15) के दौरान अपनाया गया था।
- ▶ लक्ष्य 3 का उद्देश्य 2030 तक भूमि, जल और समुद्र के 30% हिस्से का संरक्षण करना है।

ब्रिक्स (BRICS) संसदीय फोरम

हाल ही में ब्रासीलिया (ब्राजील) में 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम आयोजित किया गया।

- ▶ भारत को अगले साल 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया।

ब्रिक्स संसदीय फोरम के बारे में:

- ▶ उद्देश्य: ब्रिक्स सदस्य देशों की संसदों के बीच विधायी सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।
- ▶ पहला ब्रिक्स संसदीय फोरम 2015 में रूस की अध्यक्षता में मास्को में आयोजित किया गया था।
- ▶ ब्रिक्स के बारे में:
 - ▶ स्थापना: ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में सबसे पहले 'ब्रिक्स' (BRICs) शब्दावली का उपयोग किया था। उन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया था।
 - ⊕ ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह का सदस्य बना।
- ▶ वर्तमान सदस्य: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।

AI रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी (RAM)

यूनेस्को और MeitY ने भारत में AI रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी (RAM) पर 5वीं हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की।

AI RAM पहल के बारे में:

- ▶ यह एक व्यापक फ्रेमवर्क है, जिसे यूनेस्को और इंडिया AI मिशन (MeitY) ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के AI इकोसिस्टम की तत्परता का आकलन करना है।
- ▶ AI RAM एक नैदानिक उपकरण की भांति कार्य करता है। यह सरकारों की AI से जुड़ी नियामक और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करता है।
- ▶ इसका उद्देश्य एक भारत-विशिष्ट AI नीति रिपोर्ट तैयार करना है, जो सभी क्षेत्रों में AI के नैतिक और जिम्मेदार अंगीकरण हेतु कार्रवाई योग्य सिफारिशें पेश करना है।



चिनाब रेलवे ब्रिज

प्रधान मंत्री ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने अंजी नदी पर भारत के पहले केबल-स्टेन्ड रेल पुल "अंजी ब्रिज" का उद्घाटन भी किया।

- अंजी, चिनाब की एक सहायक नदी है।
- चिनाब या चंद्रभागा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी चंद्र और भागा नामक दो जल-धाराओं से मिलकर बनी है। ये दोनों जल धाराएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास टांडी में मिलती हैं।

चिनाब रेल ब्रिज के बारे में

- ऊंचाई और लंबाई: चिनाब नदी के जलस्तर से 359 मीटर ऊपर और 1,315 मीटर लंबा।
- मुख्य विशेषताएं: इस स्टील आर्क ब्रिज को भूकंप और पवन की प्रबल गति को सहने में सक्षम बनाया गया है।
 - ⊕ यह जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा।
- अंजी और चिनाब, दोनों पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का हिस्सा हैं।



G-7

कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को आगामी G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन कनाडा के कनानसकीस में आयोजित होगा।

G-7 के बारे में:

- स्थापना: G-7 की स्थापना 1975 के तेल संकट को देखते हुए इससे निपटने के लिए की गई थी।
- अनौपचारिक समूह: यह सात देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसके सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम।
 - ⊕ 1998 में रूस के शामिल होने से यह G-8 बन गया था। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और यह समूह फिर से G-7 बन गया।
 - ⊕ यूरोपीय संघ भी इसके शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है।
- उद्देश्य: विदेश नीति, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति आदि पर चर्चा करना।
- G-7 देशों की सामूहिक रूप से वैश्विक GDP में 40% की हिस्सेदारी है, जबकि दुनिया की केवल 10% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है।



अमीबा

केरल राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने घातक अमीबा की पहचान के लिए आणविक (मॉलिक्यूलर) परीक्षण विकसित किए हैं।

अमीबा के बारे में

- अमीबा एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यह प्रोटोजोआ नामक जीवों के समूह से संबंधित है।
- पर्यावास: अमीबा ताजे जल, समुद्री जल, मिट्टी, और मानव-निर्मित जल प्रणालियों में पाया जाता है।
- संरचना और गति: इसका आकार अनियमित होता है। यह गति करने और आहार ग्रहण करने के लिए स्फूडोपॉडिया का उपयोग करता है। स्फूडोपॉडिया इसके साइटोप्लाज्म का अस्थायी विस्तार हैं।
- पोषण: अमीबा एक परपोषी जीव है। यह आहार के लिए बैक्टीरिया, शैवाल, पादप कोशिकाओं और सूक्ष्म प्रोटोजोआ पर निर्भर हैं।
- प्रजनन: अमीबा अलैंगिक रूप से बाइनरी फिशन नामक प्रक्रिया से प्रजनन करता है।
 - ⊕ प्रजनन में पहले नाभिक का माइटोसिस द्वारा विभाजन होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म (साइटोकाइनेसिस) का विभाजन होता है।
 - ⊕ इससे दो समान अमीबा कोशिकाएं बनती हैं।



उम्मीद (UMEED) पोर्टल

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने वक्फ संपत्तियों के रीयल-टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए 'उम्मीद' केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया।

- वक्फ का आशय ऐसी किसी भी चल या अचल संपत्ति से है, जिसका उपयोग मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या नेक कार्यों के लिए किया जाता है।

उम्मीद (UMEED) पोर्टल के बारे में:

- कानून: यह एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development - UMEED Act, 1995) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- प्रमुख विशेषताएं: सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के साथ एक डिजिटल इन्वेंट्री का निर्माण, ऑनलाइन शिकायत निवारण, GIS मैपिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- महत्व: यह पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। साथ ही यह वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करता है; जैसे कि स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं, आजीविका सृजन और सामाजिक कल्याण में भागीदारी।



पांड्य कालीन शिलालेख

तमिलनाडु के मेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल प्राचीन शिव मंदिर और दो शिलालेख मिले हैं।

शिलालेखों के बारे में

- समय काल: 1217-1218 ई. के ये शिलालेख मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम के शासनकाल के हैं।
 - ⊕ मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम 1216 ई. में सिंहासन पर आसीन हुए। इसने चोल साम्राज्य पर भी आक्रमण किया।
 - ⊕ मारवर्मन ने कलियुगरमण और आदिसयापंडियादेवन और सोनादुगोंडन (चोल देश के विजेता) की उपाधियां धारण की।
- मुख्य निष्कर्ष
 - ⊕ शिलालेख में एक जल स्रोत "नागनकुडी" की बिक्री का विवरण है, जिसे 64 कासु (मुद्राएं) में बेचा गया था।
 - ⊕ इससे मंदिर का नाम "तेन्नवनीश्वरम" होने का पता चलता है।
 - ◆ "तेन्नवन" पांड्य शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि थी।
 - ⊕ इस शिलालेख में उडमपट्टी नामक स्थान का प्राचीन नाम "अत्तूर" मिलता है।

